17 फीसद तक खर्च रेल परियोजनाओं में कम हो सकता है ड्रोन का इस्तेमाल करने से। फिक्की की रिसर्च के मुताबिक, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, तेल व गैस, सौर ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन के इस्तेमाल से वहां होने वाले खर्च को घटाया जा सकता है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 22 जुलाई 2019

गरुड़ गंगा के पत्थरों पर गरमाई सियासत

- नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने लोस में किया था गरुड़ गंगा के पत्थरों की मान्यता का जिक्र
- सांसद भट्ट ने साफ किया कि उनके द्वारा शोध के मकसद से किया गया था मान्यताओं का उल्लेख

राज्य ब्यूरो, देहरादून

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक-2019 पर चर्चा के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट के चमोली की गरुड़ गंगा के पत्थरों की मान्यता को लेकर दिए गए वक्तव्य से सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली और कहा कि भट्ट ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इस संबंध में बोला होगा। हालांकि, सांसद भट्ट ने शनिवार को साफ किया था कि उनके द्वारा मेडिकल को कोई चैलेंज नहीं किया। शोध के मकसद से गरुड़ गंगा के पत्थरों को लेकर किंवदंतियों का जिक्र किया था। इसके साथ ही सवाल किया कि यह बात उन्होंने 27 जून को सदन में कही थी। इतने दिन बाद इसे क्यों तूल दिया जा रहा है, यह बात समझ से परे है। वहीं, विशेषज्ञों का भी कहना है कि विज्ञान की कसौटी पर परखने के लिए गरुड़ गंगा के पत्थरों से उपचार अथवा उसके गुणों को लेकर शोध की जरूरत है।

शुक्रवार को सोशल मीडिया में सांसद भट्ट के लोकसभा में दिए गए गरुड़ गंगा से संबंधित वक्तव्य का वीडियो वायरल हुआ। विपक्ष ने भी इस मसले को लपकने में देरी नहीं की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि अगर गरुड़ गंगा के पत्थर इतने चमत्कारिक हैं तो सीएम को इन्हें राज्य के सभी अस्पतालों में रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने सांसद भट्ट का बयान सुना नहीं था, मगर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इससे लगता है कि भट्ट ने अपने निजी अनुभवों पर ही ऐसा बोला होगा। पत्थरों से कोई चमत्कार होता है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, न ही इसका कोई वैज्ञानिक आधार है। सांसद भट्ट ने कहा कि उनके द्वारा एलोपैथी अथवा किसी भी चिकित्सा पद्धति को चुनौती नहीं दी गई। संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने किंवदंती का उल्लेख करते हुए ये बातें शोध के मकसद से कही थीं।

उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र डोभाल का कहना है कि विज्ञान किसी भी विधि को लागू करने से पहले उसका प्रमाण मांगता है। जहां तक गरुड़ गंगा के पत्थरों से इलाज या उसके गुणों की बात है तो इसके लिए शोध की जरूरत है। बिना शोध ऐसी बातों का कोई आधार नहीं है।

यह कहा था सांसद भट्ट ने : ...जैसे होम्योपैथी में मिरक्कल है, वैसे ही आयुर्वेद में भी हैं।...जितनी भी पैथी हैं, वो एक से बढ़कर एक हैं। चमोली की गरुड़ गंगा की जानकारी कम लोगों को होगी। मान्यताएं हैं कि उसके पत्थर को अंदर लाते हैं तो घर में सांप और बिच्छू नहीं आते हैं। अगर सांप-बिच्छू काट दे तो पत्थर घिसकर लगा दो। अगर मेरी कोई बहन का प्रसव काल हो और डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन करो तो पत्थर को घिसके एक कप पानी पिला दीजिए। नॉर्मल प्रसव हो जाता है।

'पबजी' को रोकने में छग सरकार ने जताई असमर्थता

- स्कूल से लेकर विधानसभा तक गूंजा पबजी गेम का मुद्दा
- विधायक कुलदीप जूनेजा ने कहा- हिंसक हो रहे हैं बच्चे

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पबजी का मुद्दा गूंजने लगा है। स्कूलों में बच्चों के हिंसक होने की खबरों के बीच अब रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप जूनेजा ने इसे विधानसभा में उठाया है। विधानसभा के मानसून सत्र में जूनेजा ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से पबजी का मुद्दा उठाते हुए कहा, देश के कई राज्यों में बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले इस गेम को प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस दिशा में कोई कार्रवई नहीं की जा रही है। इस कारण से यहां पर अभी भी स्कूलों में छात्र-छात्राएं इस मोबाइल गेम को खेल रहे हैं। इस कारण से उनमें हिंसक प्रवृत्ति घर करती जा रही है।

मोबाइल खेल पबजी को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वह रोक लगाने में सक्षम नहीं है। इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई प्रस्ताव भी विभाग के पास नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि इस खेल को प्रतिबंधित करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है। इस खेल को प्रतिबंधित करने में स्कूल शिक्षा विभाग स्वयं में सक्षम नहीं है। शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों में जागरूकता लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल, स्कूलों में पबजी खेलने के कारण बच्चों में हिंसा की भावना आ रही है। इसके कारण कई बच्चे दुर्घटना के शिकार भी हो चुके हैं।

गेम के चक्कर में बना चोर

हाल ही में कोरबा में एक मामला सामने आया था। पबजी गेम की लत ने एक किशोर को पुलिस के लॉकअप तक पहुंचा दिया था। गेम खेलने का जुनून उस पर इस कदर हावी हुआ कि उसने मोबाइल तक चोरी करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब इस संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि उसने पबजी गेम की चक्कर में मोबाइल की चोरी की है।

पूर्व विधायकों की अटकी पेंशन सात माह से कर रहे इंतजार

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायकों की पेंशन अटक गई है। राज्य में नई सरकार बनने के सात महीने बाद भी विधायकों की पेंशन की कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई है। अब विधायक पेंशन के लिए विधानसभा सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि विधानसभा की ओर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नियंत्रक महालेखपरीक्षक (सीएजी) के पास फाइल अटकने के कारण पूर्व विधायकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा सचिव चंद्रशेखर गंगराडे ने बताया कि सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है। संभवतः अगस्त से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

कोरबा जिला कटघोरा के पूर्व विधायक लखन लाल, रामपुर के श्यामलाल और पाली तनाखार के रामदयाल उइके को पेंशन नहीं मिल रही है। विधायकों ने बताया कि शासन से पत्र भेजा गया है, जिसमे जल्द पेंशन प्रदान करने की बात कही गई है। बैकुंठपुर की पूर्व विधायक चंपादेवी पावले, भइयालाल राजवाडे व श्यामबिहारी जायसवाल हैं, जिनकी पेंशन प्रारंभ नहीं हुई है। रायगढ़ जिले के तीनों पूर्व विधायक रोशन अग्रवाल, सुनीति राठिया व केराबाई को अब तक पेंशन नहीं मिल रही है। केराबाई प्रदेश की सबसे गरीब पूर्व विधायकों में से एक हैं। पिछले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। जांजगीर में पूर्व विधायक अंबेश जांगडे, मोतीलाल देवांगन व चुन्नीलाल साहू की भी अब तक पेंशन प्रारंभ नहीं हुआ है। विधायकों ने कहा कि वे सभी कागजी कार्यवाही पूरी कर चुके हैं। विधानसभा सचिवालय से पूछने पर आश्वासन ही मिलता है। कई विधायकों ने कहा कि पेंशन शुरू नहीं होने पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पांच साल तक विधायक रहने वालों को 20 हजार रुपये पेंशन का प्रावधान है।

पति की बेगुनाही साबित करने को विधायकों का समर्थन जुटा रहीं रामबाई

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद लगातार सुर्खियों में रही बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई पति गोविंद सिंह की बेगुनाही के लिए विधायकों का समर्थन जुटा रही हैं। चार महीने पहले हुई देवेंद्र चौरसिया की हत्या के प्रकरण की जांच के लिए रामबाई अब एसआइटी गठित कराने की मांग कर रही हैं। उनका दावा है कि इसके समर्थन में वह भाजपा और कांग्रेस के 75 विधायकों के दस्तखत करा चुकी हैं। बता दें कि गोविंद सिंह का नाम इस हत्याकांड के आरोपितों में है। हालांकि कांग्रेस दावा कर चुकी है कि उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं है।

'नईदुनिया' से चर्चा में रामबाई ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस मामले में न्याय की मांग की है। वह हर तरह की जांच कराने को तैयार हैं। एसआइटी गठन के लिए ज्ञापन पर विधायकों के दस्तखत ले रही हूं। सभी विधायकों का समर्थन हासिल कर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर एसआइटी से जांच की मांग करूंगी। रामबाई के पति गोविंद सिंह का भी आरोप है कि क्षेत्र के भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने उसके खिलाफ साजिश कर आरोपितों में उनका नाम भी जुड़वा दिया, जबकि वह हत्यारों में शामिल नहीं हैं।

बसपा बाहर से देगी समर्थन : पिप्पल : बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल का कहना है कि रामबाई कुछ भी कहें, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का निर्णय स्पष्ट है कि पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। मप्र की कमलनाथ सरकार को बसपा बाहर से ही समर्थन देगी, इस पर पार्टी अब भी कायम है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि रामबाई के पति पर दर्ज प्रकरण के संदर्भ में संगठन प्रमुख के नाते उन्होंने भी पूछताछ की है, जिसमें विधायक ने यही बताया कि उनके खिलाफ साजिश की गई है।

प्रियंका पर निर्भर है सिद्धू का राजनीतिक भविष्य

संभावनाएं ▸ कैबिनेट से इस्तीफे के बाद एआइसीसी में मिल सकता है अहम पद

सिद्धू की कांग्रेस में एंट्री कराने में भी रही थी प्रियंका की अहम भूमिका

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

प्रियंका गांधी वाड्रा फाइल फोटो

नवजोत सिंह सिद्धू फाइल फोटो

पंजाब कैबिनेट की पिच पर नवजोत सिंह सिद्धू अर्द्ध शतकीय पारी खेल कर आउट हो चुके हैं। अब उनके पास पवेलियन में बैठकर मैच देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिद्धू कांग्रेस की टीम में बने रहेंगे, इसका फैसला अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के भविष्य पर तय करेगा। राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस का एक वर्ग प्रियंका में अपना नया अध्यक्ष ढूंढ़ रहा है। ऐसे में प्रियंका सिद्धू को कांग्रेस की टीम में बनाए रखने के लिए अहम फैसला ले सकती हैं। उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) में अहम ओहदा मिल सकता है।

अहम बात यह है कि सिद्धू का इस्तीफा भी उसी समय हुआ है, जब प्रियंका कांग्रेस में अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं। सिद्धू को कांग्रेस में लाने के पीछे भी प्रियंका ही थीं। उन्होंने सिद्धू का कैबिनेट ओहदा बरकरार रखने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस में चल रही उठापटक के चलते वह भी सिद्धू की मदद नहीं कर पाईं। सिद्धू ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी से नहीं। ऐसे में सिद्धू के पास 'वेट एंड वॉच' की नीति अपनाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर प्रियंका के हाथ में कांग्रेस की कमान आती है, तो सिद्धू को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कैबिनेट से आउट होने से कांग्रेस का एक बड़ा तबका राहत की सांस ले रहा है। उनकी कांग्रेस में एंट्री के समय भी कई वरिष्ठ नेता खुश नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से आने वाले सिद्धू का बड़बोलापन कांग्रेस के एक वर्ग को कभी रास नहीं आया। कांग्रेस में एंट्री के साथ ही सिद्धू ने जो तेवर दिखाए थे, उससे लगातार यह संकेत मिल रहे थे कि कांग्रेस में उनका भविष्य सुनहरा नहीं है, क्योंकि सिद्धू ने अपने आक्रामक तेवर से कई फ्रंट खोल लिए थे। अकाली दल को घेरते-घेरते सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी सीधी टक्कर ले ली।

बार-बार गलतियों से बढ़ी मुश्किल : ढाई साल में तीन ऐसे मौके आए जब सिद्धू की वजह से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान जाकर वहां के सेना प्रमुख को गले लगाना, अमरिंदर सिंह को अपना कैप्टन मानने से इन्कार करना और बठिंडा में पार्टी के विरोध में टिप्पणी करना जैसे मामलों से उनकी काफी किरकिरी हुई। सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद इस बात की संभावना कम ही है कि कांग्रेस सिद्धू को पंजाब में कोई बड़ा ओहदा दे।

सिद्धू अमृतसर पहुंचे, मीडिया से नहीं की बात

जासं, अमृतसर: पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू और बेटी राबिया सिद्धू रविवार शाम अमृतसर स्थित अपने निवास पर पहुंचे। सिद्धू कड़ी सुरक्षा में कोठी के अंदर पहुंचे और अंदर पहुंचते ही सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की और कोठी के तीनों गेट बंद कर दिए।

बिहार में भाजपा को जदयू की सलाह गठबंधन विरोधी बयान बर्दाश्त नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना : जदयू के राष्ट्रीय महासचिव पवन वर्मा ने भाजपा नेतृत्व से कहा है कि वह बिहार में गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करने वाले अपने सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक, विधान परिषद सदस्य और पार्टी नेताओं पर लगाम लगाए। इस प्रकरण पर भाजपा नेतृत्व स्पष्ट करे कि ऐसे बयान इन नेताओं के निजी हैं या पार्टी के नेतृत्व की सहमति से यह सब हो रहा है।

वर्मा ने रविवार को दैनिक जागरण को फोन पर बताया कि भाजपा के कुछ नेताओं का गठबंधन विरोधी बयान बर्दाश्त करने की सीमा को पार कर रहा है। उनके बयान में सत्ता का मद और अहंकार साफ झलक जाता है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नेतृत्व को लग रहा है कि वह अकेले विधानसभा चुनाव लड़कर कामयाब हो जाएगी तो वह स्पष्ट निर्णय ले। यह भाजपा का फैसला होगा। जहां तक जदयू का सवाल है, पार्टी हर चुनौती के मुकाबले के लिए तैयार है।

जदयू के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जदयू को अपनी मर्यादा का ज्ञान है और यह भी पता है कि मर्यादा के पालन के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू-भाजपा गठबंधन को राज्य में शानदार उपलब्धि हासिल हुई। इसके बाद भाजपा के नेता जिस तरह का बयान दे रहे हैं, वह कहीं से उचित नहीं है।

आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमों में साक्ष्य जुटाने में लगी पुलिस

- जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज हो चुके हैं 27 मुकदमे
- विशेष जांच टीम गठित, किसानों की जमीन के मांगे रिकार्ड

जागरण संवाददाता, रामपुर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद आजम खां के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज हुए 27 मुकदमों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस मुकदमे से संबंधित साक्ष्य जुटा रही है। इसके लिए राजस्व विभाग से किसानों की जमीनों के रिकार्ड तलब किए गए हैं।

मुकदमे में सांसद के अलावा आरोपित इंस्पेक्टर कुशलवीर सिंह से भी पुलिस ने पूछताछ की है। कुशलवीर अजीमनगर थाना प्रभारी रहे हैं और वर्तमान में वह बदायूं जिले के थाना सहसवान में तैनात हैं। इन मुकदमों में सांसद और इंस्पेक्टर के अलावा जौहर यूनिवर्सिटी में मुख्य सुरक्षा अधिकारी पूर्व सीओ आले हसन खां भी नामजद हैं। एक बार गिरफ्तारी के लिए यूनिवर्सिटी स्थित आवास पर भी दबिश दी थी। उनके न मिलने पर पुलिस उनके बेटे वसीम को पकड़ लाई थी। दबिश के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस से अभद्रता के आरोप में मुकदमा दर्ज कर बेटे वसीम को जेल भेज दिया था।

यह है मामला : सांसद आजम खां ने करीब 15 साल पहले जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। वह यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर हैं। अजीमनगर थाने में दर्ज मुकदमों में सांसद पर आरोप है कि जमीनों पर जबरन कब्जा कर उन्हें यूनिवर्सिटी में मिला लिया है। इसके लिए किसानों पर पहले बैनामा कराने के लिए दबाव बनाया गया। पुलिस ने चरस, स्मैक जैसे मुकदमों में जेल भेजने की धमकी दी। मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. अजयपाल शर्मा ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। थाना अजीमनगर प्रभारी राजीव चौधरी ने बताया कि मुकदमों से संबंधित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

आजम खां फाइल फोटो

उपचुनाव जीतने के लिए जुल्म की हदें की पार : डॉ. तजीन : सांसद आजम खां की पत्नी एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए शासन और प्रशासन ने रामपुर में जुल्म की हदें पार कर दी हैं। आजम खां की छवि खराब करने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्हें भूमाफिया घोषित किया गया है। इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे और लोकसभा व राज्यसभा में भी मुद्दे को उठाएंगे। रविवार को अपने आवास पर मीडिया से वार्ता के दौरान राज्यसभा सदस्य ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में एक-एक इंच जमीन खरीदी गई है।

आजम के खिलाफ राजभवन पहुंचे किसान : सपा सांसद आजम खां के खिलाफ शिकायती पत्र लेकर रामपुर के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को राजभवन में राज्यपाल राम नाईक से मिला। किसानों और अल्पसंख्यकों को बेघर करने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि पूरे प्रकरण से मुख्यमंत्री को न सिर्फ अवगत कराएंगे बल्कि पत्र लिख कर कार्रवाई की सिफारिश भी करेंगे।

जनाधार बढ़ाने के लिए अब ग्रामीण स्तर पर अभियान चलाएगी कांग्रेस

- जम्मू-कश्मीर में गांवों में सदस्यता अभियान के जरिये अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

गुलाम नबी आजाद फाइल फोटो

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत करने के लिए ग्रामीण स्तर पर अभियान चलाएगी। इसके लिए तीन चरणों में अभियान चलाए जाएंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने रविवार सुबह जम्मू में डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भद्रवाह के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठककर पार्टी का जनाधार मजबूत करने के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

इस दौरान आजाद ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। गांवों में सदस्यता अभियान के जरिये अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। पहले चरण की शुरुआत जल्द होगी। संसदीय चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद आजाद का कश्मीर के बाद जम्मू का यह पहला दौरा था। गत दिवस उन्होंने जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी व अन्य इलाकों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर जमीनी स्तर पर काम करने पर जोर दिया था। रविवार सुबह उन्होंने बैठक कर नेताओं से पार्टी में एकजुटता बनाए रखने, कोई गुटबाजी न करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा।

आजाद ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। इसके लिए अभी से जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए। प्रमुख मुद्दों को उठाया जाए। हमें अपने मनोबल को गिराना नहीं है। उत्साह के साथ लोगों के बीच जाना है। पार्टी के मुद्दों से कोई समझौता नहीं करना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नाकामियों और पूर्व पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के खोखले वायदों को भी लोगों के बीच लेकर जाना है। आजाद ने कहा कि उनका अगला दौरा लद्दाख का होगा। राज्य के तीनों क्षेत्रों पर पार्टी पूरा ध्यान देगी। विधानसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा कि किसी से गठजोड़ करना है या नहीं। हमें पहले पार्टी को मजबूत करना है। आजाद बैठक के बाद दिल्ली लौट गए। बैठक में उनके साथ प्रदेश प्रधान जीए मीर, पूर्व मंत्री रमण भल्ला, विक्रमादित्य सिंह, रविंद्र शर्मा व अन्य शामिल थे।

माकपा के गुंडे, भाजपा के उस्ताद

▸ पहले पेज का शेष

दीदी ने एक बार फिर कांग्रेस व माकपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बंगाल में माकपा व कांग्रेस जिस डाल पर बैठे हुए हैं, उसे न काटे। जो पहले माकपा के हर्मद (गुंडे) थे, वे इस समय भाजपा के उस्ताद बन गए हैं। हत्या व अपराध करने वाले कोई नहीं बचेंगे, चाहे वे भाजपा में क्यों न चले जाएं। ममता ने आगे कहा कि उन्हें माकपा व कांग्रेस की जरूरत नहीं है, हालांकि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह जरूर कहा कि अब भी माकपा में बचे हुए कुछ अच्छे लोग हैं, उन्हें पार्टी से जोड़ें।

भाजपा पर खरीद-फरोख्त का आरोप : मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा धन और अन्य प्रलोभनों के जरिये तृणमूल के विधायकों को ललचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, 'भाजपा पाला बदलने की स्थिति में हमारे विधायकों को दो करोड़ रुपये और एक पेट्रोल पंप देने की पेशकश कर रही है। कर्नाटक की तरह, भाजपा हर जगह खरीद-फरोख्त में शामिल है।'

मोदी सरकार ने पांच साल में बदल दिया देश, आए 'अच्छे दिन' : नड्डा

मुंबई, प्रेट्र : भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को यहां एक कार्यक्रम में दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में देश बदल गया है और 'अच्छे दिन' आ गए हैं। उन्होंने दोहराया कि जब भाजपा कहती है कि उसका लक्ष्य कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का है तो उसका मतलब है कि वह भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहती है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की उपस्थिति में भाजपा की महाराष्ट्र प्रदेश कार्यसमिति की यहां हुई बैठक में नड्डा ने कहा, 'अच्छे दिन आने वाले हैं और देश बदल रहा है, वर्ष 2014 में भाजपा के चुनावी अभियान के नारे थे। आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अच्छे दिन आ गए हैं और पिछले पांच वर्षों में देश बदल चुका है।' उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है।

नड्डा ने कहा, 'कांग्रेस मुक्त भारत से हमारा आशय भ्रष्टाचार व कमीशन मुक्त भारत से है, पार्टी से नहीं। इसी तरह भाजपा युक्त भारत का मतलब है विकास उन्मुखी भारत है। इसका मतलब है- सेवा व विकास पर ध्यान केंद्रित करना, निचले स्तर पर कार्य करना और केवल खुद की उन्नति के लिए काम नहीं करना।'

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 व 2019 में मिली बड़ी जीत ने वोट बैंक व जाति की राजनीति को खारिज कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं का उद्देश्य होना चाहिए कि वे दुनिया को देखें और स्थानीय स्तर पर कार्य करें।

उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 से पहले विदेश में भारत की छवि एक भ्रष्ट देश के रूप में थी, जो लकवाग्रस्त विदेश नीति और दिशाहीनता का शिकार था। अब विदेश में रहने वाले भारतीय गर्व महसूस करते हैं। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात, इजरायल, रूस व सऊदी अरब जैसे देशों ने सम्मानित किया है।

सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए करें तैयारी : पाटिल

बैठक के दौरान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कार्यकर्ताओं से प्रदेश की सभी 288 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, 'समझौते और सीटों के बंटवारे का काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस व पार्टी प्रमुख अमित शाह पर छोड़ दें। तैयारी ऐसी हो कि अगर किसी सीट पर हमारा साझीदार लड़े तो भी जीते।

तैयारी

25 को होने वाली बैठक में शामिल होंगे पांच राज्यों के मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल भेजेंगे अपना प्रतिनिधि

ड्रग्स के विरुद्ध राष्ट्रीय नीति पर समर्थन जुटाएंगे कैप्टन

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल फोटो

ड्रग्स के विरुद्ध रणनीति तैयार करने के लिए 25 जुलाई को होने वाली पांच उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक काफी अहम रहेगी। माना जा रहा है कि ड्रग्स तस्करों से जुड़ी जानकारी आपस में शेयर करने के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बैठक में ड्रग्स पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर करेंगे, क्योंकि कैप्टन शुरू से ही केंद्र सरकार से ड्रग्स के मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। चूंकि अभी तक यह मांग केवल पंजाब की तरफ से उठती रही है इसलिए अब दूसरे राज्यों से भी समर्थन जुटाने की पहल की जा सकती है।

जम्मू-कश्मीर से वहां के राज्यपाल अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक को लेकर पहले ही अपनी स्वीकृति दे दी थी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी स्वीकृति दी हुई है। पंजाब सरकार इस बैठक को सफल बनाने की तैयारी में जुट गई है। पंजाब के लिहाज से यह बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ड्रग्स का ट्रांजिट रूट होने के कारण पंजाब इससे काफी प्रभावित है। ड्रग्स की समस्या भले ही पूरे देश की हो, लेकिन पंजाब में ड्रग्स पिछले एक दशक से राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है। ड्रग्स सप्लाई की कमर तोड़ने के लिए पंजाब सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) भी बनाई है।

एकजुट करना होगी चुनौती : अगर 25 जुलाई को होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में राष्ट्रीय नीति बनाने को लेकर आम सहमति बनती है, तो इससे केंद्र सरकार पर दबाव भी बनेगा। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जबकि हिमाचल प्रदेश व हरियाणा में भाजपा की, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ऐसे में ड्रग्स के ऊपर राष्ट्रीय राजनीति बनाने के लिए सभी को एक मत करना कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि, 12 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ड्रग्स को लेकर होने वाली बैठक को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को सकारात्मक संकेत दिए थे।

केजरीवाल और गहलोत के रुख पर खास नजर

सबसे अहम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रुख होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने पंजाब में ड्रग्स को ही अपना चुनावी एजेंडा बनाया था। ऐसे में देखना होगा कि केजरीवाल पंजाब सरकार के एजेंडे का समर्थन करते हैं या नहीं। वहीं, राजस्थान में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन वहां पर अफीम की खेती करना वैध है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या रुख होगा, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा।

गरीबों के मकान हथियाने का चल रहा रैकेट, जांच हो : आकाश विजयवर्गीय

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के इंदौर में बल्लाकांड से चर्चित हुए विधायक आकाश विजयवर्गीय पहली बार विधानसभा में बोले तो इस कांड से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करना नहीं भूले। रविवार को विधानसभा में नगरीय विकास विभाग की बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर में कुछ प्रभावी लोगों द्वारा गरीबों के मकानों को जर्जर बताकर छीना जा रहा है। उन्हें तोड़कर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि, आकाश ने पिछले दिनों हुए बल्लाकांड का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जर्जर मकानों को तोड़कर प्रभावी लोगों को दिया जा रहा है। यह एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। मालूम हो, पिछले दिनों इंदौर में नगर निगम द्वारा एक जर्जर भवन को तोड़ने की कार्रवाई का आकाश विजयवर्गीय ने विरोध किया था और इस दौरान निगम के एक कर्मचारी को क्रिकेट के बल्ले से मारा भी था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को इस कांड के बाद आलोचना झेलनी पड़ी थी।

पीडीपी को अलविदा कह पूर्व मंत्री बंड नेकां में हुए शामिल

- राज्यसभा के पूर्व सदस्य जीएन रतनपुरी ने नेकां से त्यागपत्र दिया

राज्य ब्यूरो, जम्मू

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के संस्थापक सदस्य और पूर्व मंत्री मुहम्मद खलील बंड रविवार को नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) में शामिल हो गए। बंड के नेकां में जाने के चंद घंटों बाद राज्यसभा के पूर्व सदस्य जीएन रतनपुरी ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

रविवार को श्रीनगर में पार्टी कार्यालय नवा-ए-सुवा में आयोजित कार्यक्रम में नेशनल कांफ्रेंस में शामिल हुए बंड ने बीते बुधवार को पीडीपी से त्यागपत्र दिया था। उन्होंने लिखा था कि मुफ्ती मुहम्मद सईद के निधन के बाद पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है। अब पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। कुछ नेता अपने निहित स्वार्थों के लिए जो कदम उठा रहे हैं, उससे पार्टी का जनाधार कम हुआ है। बंड पीडीपी की टिकट पर पुलवामा विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विजयी हुए हैं। वह पीडीपी-भाजपा सरकार में मंत्री भी थे।

नेशनल कांफ्रेंस के प्रधान डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी में बंड का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे पार्टी को राज्य में और मजबूती मिलेगी। अभी पार्टी में बंड के शामिल होने का समारोह खत्म ही हुआ था कि राज्यसभा के पूर्व सदस्य जीएन रतनपुरी ने नेशनल कांफ्रेंस छोड़ने की घोषणा कर दी।

पार्टी प्रधान डॉ. फारूक अब्दुल्ला के नाम पत्र लिखा कि वह पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। वह उपप्रधान, महासचिव तथा जम्मू-कश्मीर के प्रांतीय प्रधानों से कहें कि उनके पार्टी छोड़ने पर भी सम्मान दें जैस कि पार्टी में शामिल होने के दौरान दिया गया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि पिछले दस वर्ष के दौरान उनकी पार्टी में किसी से भी किसी भी प्रकार का अगर कोई मतभेद रहा होगा तो वे उसे भुला देंगे।